भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1681

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना

1681. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक विशेषकर बंगलुरू के अंतर्गत स्वीकृत, चल रहे और पूर्ण किए गए मकानों की संख्या कितनी है और इन आवासों के पूरा होने से कितने परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी राजसहायता अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगलुरु में योजना के विस्तार के लिए कितने भूभाग की पहचान की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए लागू किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों/परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से लागू किया जाता है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

पीएमएवाई-यू के तहत**, 15.07.2024** तक कर्नाटक राज्य के लिए कुल **6,38,121** आवासों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 5,73,160 आवास निर्माणाधीन हैं और जिसमें से 3,69,449 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। बेंगलुरु में**,** इस योजना के तहत **1,51,795** आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से **1,35,586** आवास निर्माणाधीन हैं और 85,166 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

कर्नाटक के लिए कुल **10,614.43** करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई हैं, जिसमें से **7,168.29** करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं। इसमें से बंगलौर के लिए **2,682.58** करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है**,** जिसमें से मंत्रालय द्वारा **2,121.29** करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं।

*****